

दिल्ली-जोधपुर मेल

1742. श्री प० ल० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जोधपुर मेल बन्द कर देने की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या राय है ;

(घ) क्या यह सच है कि घग्गर नदी में बाढ़ के कारण इस वर्ष भी सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के पास की रेलवे लाइन टूट गई थी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सेक्शन में लाइनों के इस प्रकार टूटने को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). 93 अप/94 डाउन जोधपुर मेल गाड़ियाँ इस समय जिस रास्ते से चलती हैं, उसमें कठित परिवर्तन के विरुद्ध में अभ्यावेदन मिले हैं। लेकिन इस समय इन गाड़ियों को न तो किसी दूसरे रास्ते से चलाने का प्रस्ताव है और न इन्हें बन्द करने का।

(घ) 27 जुलाई, 1964 से घग्गर नदी में बाढ़ के कारण इस वर्ष भी सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के पास रेलवे लाइन टूट गयी थी।

(ङ) घग्गर नदी की बाढ़ का पानी निकालने के लिए एक मोड़ नाली बनाने की योजना को राजस्थान सरकार अन्तिम रूप दे रही है।

Iron Ore Deposit in Lahora Mine

1743. Shri Himatsingka: Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state:

(a) the approximate amount of de-

posit of iron in the Lahora Mine in the district of Chanda (Maharashtra State);

(b) whether it is a fact that the mine was working regularly and about 2,000 labourers were engaged therein;

(c) whether it is working now; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) to (d). The lease of Lahora Iron Ore mine which was held by a private party was terminated by the Government of Maharashtra in August, 1961. Against the order of the State Government, the lessee submitted a review petition to the Central Government which was also rejected. The lessee has now filed a Writ Petition in the Punjab High Court. The matter is, therefore, sub-judice.

Small Scale Industries

1744. { Shri Vidya Charan Shukla:
Shri R. S. Pandey:
Shri Uikay:

Will the Minister of Industry and Supply be pleased to state:

(a) whether the Development Commissioner, Small Scale Industries had assessed the capacities of small scale units consuming non-ferrous metals sometime in February-March, 1964;

(b) whether this assessment was done in order to make allocations of non-ferrous metals to the States on above basis;

(c) whether the State-wise allocation of non-ferrous metals for the period April-September, 1964 has been made accordingly; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri

Bibudhendra Misra): (a) The assessment of capacities of small scale units consuming non-ferrous metals has not yet been finalised;

(b) The assessment is being done to ascertain the requirements of various States for non-ferrous metals;

(c) and (d). The question of making the allocations on the basis of assessed capacity is still under consideration.

Derailment near Gauhati Station

1745. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the engine of a passenger train derailed near Gauhati Station (N.F. Railway) on the 18th August, 1964;

(b) if so, the cause of the derailment; and

(c) the damage caused thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):

(a) Yes.

(b) The accident was due to failure of mechanical equipment.

(c) The cost of damage to railway property was assessed at approximately Rs. 861.

Katihar-Siliguri Section of N.F. Railway

1746. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether railway communications on the Katihar-Siliguri Section of N. F. Railway was disrupted due to recent floods in the area;

(b) if so, to what extent; and

(c) whether the line is proposed to be realigned and diverted along safer route away from the borders with Pakistan?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):

(a) Yes, Sir.

(b) Through communications were disrupted due to floods between Bagdogra and Thakurganj Stations on Katihar-Siliguri Section from 23.57 hrs. of 8-7-1964 to 19.10 hrs. of 10-7.64.

(c) No such proposal is under consideration.

गैर-सरकारी संस्थाओं को रेलवे पास

1747. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के प्रतिरिक्त कुछ निजी एवं अर्ध-सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को भी रेलवे के निःशुल्क पास दिये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किन सिद्धान्तों को अपनाया गया है ;

(ग) क्या किहीं निजी सगटनों एवं अर्ध-सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों के रेल पास के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और यदि हाँ, तो कब तक उन पर निर्णय हो जायेगा ; और

(घ) कितने पास दिये गये हैं तथा किन व्यक्तियों को ?

रेलवे मालय में राज्य मंत्री (श.० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) रेल कर्मचारियों को जितने और जिन नियमों के अन्तर्गत रेलवे पास और पी०टी०प्रो० दिये जाते हैं, उन्हीं के अनुसार नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन नामक अर्ध-सरकारी संस्था के कर्मचारियों को पास और पी०टी०प्रो० दिये जाते हैं, क्योंकि इस कार्पोरेशन के कर्मचारी इसकी स्थापना से पहले रेल कर्मचारी थे। लेकिन इन्हें जो पास दिये जाते हैं, उनका मूल्यांकन किया जा रहा